

अडानी है मोदी का मुख्योत्ता : केजरीवाल

फरीदाबाद (मजदूर मोर्चा) दुनिया का सबसे अमीर बनने की लालसा में कम पढ़ा लिखा होना बाधा बना तो मोदी ने अडाणी को मुख्योत्ता बना लिया। श्रीलंका, हो या बांग्लादेश हर जगह के बिजली के ठेके अडाणी को दिलाए, नियमों को ताक पर रख कर एयरपोर्ट लिए, बेहतरीन कोयले को वेस्ट बताकर मुफ्त में अडाणी को दिलवाया, देश भर के बिजली उत्पादन प्लांटों को दस प्रतिशत कोयल आयातित यानी अडाणी की कंपनी से लेने को मजबूर किया। यही कारण है कि 2014 में विश्व के अमेरिंग में 60वें नंबर से 2022 में अडाणी या यूं कहें मोदी विश्व के दूसरे नंबर के अमीर बने। यह आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद के जरीवाल ने विधानसभा सत्र में दिए भाषण में लगाए।

केजरीवाल ने सदन में सीधा आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी आजादी के बाद से देश में सबसे भ्रष्ट और सबसे कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं।

अडाणी की कंपनी में नरेंद्र मोदी का धन लगा है, मोदी को अब दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनने की तमाज़ है। जिस मोदी ने अपनी मां, भाई रिशेदारों वहाँ तक कि राजनीतिक गुरु के लिए कुछ नहीं किया वह इबूते हुए अडाणी को बचाने के लिए एसबीआई, ईपीएफओ आदि से अभी भी उसके शेरयों में धन लगाने का दबाव बना रहे हैं।

दरअसल अडाणी तो मुख्योत्ता है उसकी कंपनियों में सारा धन मोदी का है। अडाणी को तो 10 से 15 प्रतिशत कमीशन ही मिलता है वह तो मोदी का मैनेजर है। अडाणी तो मोदी का सलाहकार या मैनेजर है, सारा धन तो प्रधानमंत्री मोदी ही लगाते हैं। अगर जेपीसी, ईडी, सीबीआई जांच हुई तो अडाणी नहीं बल्कि मोदी डूबेंगे।

एक भाजपा नेता से बातचीत का हवाला देते हुए केजरीवाल ने मोदी पर श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे पर दबाव डाल कर वहाँ का विंड पावर प्रोजेक्ट अडाणी को दिलाने



का आरोप लगाया। बांग्लादेश में 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट भी अडाणी को दिलाया।

इजराइल के साथ किए गए सारे रक्षा सौदे भी अडाणी को दिलाए। अडाणी को एयरपोर्ट के प्रबंधन का कोई अनुभव नहीं था बावजूद इसके छह एयरपोर्ट अडाणी को दिला दिए। दरअसल यह सब अडाणी के नाम पर मोदी ने खुद के लिए किया। ईडी, सीबीआई का अडाणी यानी मोदी के हित में दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। अक्टूबर 2018 को कृष्णापृथ्वी पौर्ट पर इनकम टैक्स की रेड हुई, छह अप्रैल 2020 को अडाणी ने वह पोर्ट खरीद लिया। दिसंबर 2020 एसीसी, अंबुजा सीमेंट पर रेड हुई, अक्टूबर 2022 को अडाणी ने खरीदे। मुंबई एयरपोर्ट के मालिक जीवीके पर सीबीआई की रेड हुई। और एक माह बाद ही मुंबई एयरपोर्ट भी अडाणी के पास चला गया। देश में कोयला आयात करने का अडाणी का एकाधिकार है।

मोदी ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि उनके पावर प्लॉट में दस प्रतिशत कोयला अडाणी से आयातित खरीदना होगा। जो कि दस गुना महंगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनियों को कोयला खाने दिए जाने पर रोक लगा दी थीं लेकिन मोदी जी ने अडाणी पर विशेष अनुकंपा की। अडाणी को 2800 करोड़ रुपये कीमत का

कोयला बेकार बता कर प्रतिवर्ष मुफ्त में दिया जाता है।

विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति बनने की लालसा में मोदी ने देश को हर तरह से लूटा, देशवासियों को रिकॉर्ड कर्ज में लाद दिया। 1955 से 2017 तक सरकारों ने 55 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया। 2014 के बाद आई मोदी की कथित राष्ट्रवादी सरकार ने 85 लाख करोड़ रुपये कर्ज ले लिया। कर्ज के नाम पर लिया गया यह धन इन दोनों की जेब में चला गया, जिसका खामियाजा जनता को भुगतान पड़ेगा। 2014 में अडाणी यानी मोदी की है सियत 50 हजार करोड़ आंकड़ी गई थी। सात साल बाद यानी 2022 में यह साड़े ग्यारह लाख करोड़ रुपये हो गई।

मोदी जी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं लेकिन हिंदूनगर्भ की रिपोर्ट के कारण उनकी लालसा मिट्टी में मिल गई। केजरीवाल यहीं नहीं रुके उन्होंने मोदी की तुलना इतिहास में हुए अनपढ़ बादशाहों से भी कर डाली, जिनकी मूर्खता के कारण सोने की चिड़िया जैसा देश विदेशीयों द्वारा लूट लिया गया। विदेशी बादशाहों के दरबार में आने उनके गुणगान करते, चापलूसी करते और न जाने कहाँ कहाँ उनसे दस्तखत करा ले जाते थे, ऐसा ही कुछ आजकल विदेशीयों द्वारा मोदी के साथ किया जा रहा है।

जिला नेग्लिजेंस बोर्ड फरीदाबाद उल्लंघनकर्ताओं का बना संरक्षक: पीड़ितों को न्याय नहीं

फरीदाबाद मजदूर मोर्चा

जिला नेग्लिजेंस बोर्ड फरीदाबाद अयोग्य सिविल सर्जन डॉ. विनय गुप्ता की देखरेख में उल्लंघनकर्ताओं की मिलीभगत से सभी प्रोटोकॉल और नैतिकता का उल्लंघन कर रहा है जो दो मामलों में साबित हुआ है:

चिकित्सीय लापरवाही की शिकायत के मामले 79/2021 में बोर्ड ने खुद को जांच में अक्षम करार देते हुए इसे जांच के लिए पीजीआईएमएस रोहतक कर दिया। पीजीआई बोर्ड द्वारा लापरवाही के दोषी के सत्यापन के बाद खुद को अक्षम कहने वाला यह बोर्ड पीजीआईएमएस रोहतक के विरोध में अपनी राय दे रहा है तथा उल्लंघन करने वाले अस्पतालों को संरक्षण दे रहा है।

चिकित्सीय लापरवाही के दूसरे मामले 142/2022 में इसी बोर्ड का कहना है कि जिला नेग्लिजेंस बोर्ड पीजीआईएमएस रोहतक की रिपोर्ट पर अपनी राय देने में सक्षम नहीं है क्योंकि पीजीआईएमएस जिला नेग्लिजेंस बोर्ड से एक उच्च स्तरीय बोर्ड है। इसलिए इस मामले में पीजीआई की रिपोर्ट ही मान्य रहेगी।

दो अलग-अलग चिकित्सा लापरवाही मामलों की जांच में दो अलग-अलग मापदंड तथा मानक कैसे हो सकते हैं?



सिविल सर्जन डॉ. विनय गुप्ता

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।

खनन मंत्री के जिले में अरबों रुपये का अवैध खनन, कार्रवाई शून्य

-अवैध खनन रोकने के लिए विभागों के बीच नहीं है समन्वय -एफआईआर दर्ज कराने के बाद नहीं होती कोई कार्रवाई

फरीदाबाद (मजदूर मोर्चा) खनन मंत्री मूलचंद शर्मा के अपने शहर में अरबों रुपयों का अवैध खनन जारी है। शहर ही, नहर पार, अगवली का पीएलपीए संरक्षित इलाका या यमुना का किनारा सभी जगह अंधाधुंध तरीके से अवैध खनन जारी है। नियमों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा अवैध खनन का यह खेल माफिया, नेता और अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। कार्रवाई के नाम पर खनन विभाग, पुलिस, वन विभाग, हूडा, नगर निगम जैसे महकमे मूकदरशक बने हुए हैं। हाँ कभी कभार एक-दो रेत से भरे ट्रैक्टर पकड़ कर पीठ थपथपाई जाती है। यह कार्रवाई भी अधिकतर पुलिस ही करती है न कि खनन विभाग के अधिकारी। शहरी इलाके में एक मीटर से अधिक जमीन का खनन करने के लिए खनन विभाग में बाकायदा निर्धारित शुल्क जमा कर परमीशन लेनी होती है। एनआईटी एक, दो, तीन और पांच में बिल्डिंग माफिया धड़ल्ले से बेसमेंट खोद रहे हैं। रिहायशी इलाकों में तीन से चार मीटर तक मिट्टी खोदी जाती है लेकिन न तो नगर निगम और न ही खनन विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है। नहर पार इलाके में मास्टर रोड से सटी हुई जमीन अवैध रूप से आठ से दस मीटर तक खोद डाली गई लेकिन न हो रही है। हूडा के जो नए सेक्टर विकसित हो रहे हैं खनन माफिया वहाँ भी सक्रिय हैं। प्लॉट खरीदने वाले खुद तो तब ठग महसूस करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मकान बनाने से पहले उन्हें काफी मिट्टी की भरान करनी होगी, क्यों कि माफिया उनके प्लॉट से अवैध रूप से मिट्टी खनन कर ले जा चुका है। यह अवैध खनन अगवली पीएलपीए संरक्षित क्षेत्र में लगातार जारी है। खनन माफिया और भी माफिया लगातार पेड़ों में आग लगाकर जमीन समतल करने के नाम पर खुदाई कर रहे हैं। खास बात यह है कि खनन विभाग को इसकी जानकारी नहीं। अधिकारी कहते हैं कि वन विभाग का क्षेत्र है इसलिए कार्रवाई वन विभाग कराएगा। नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम, हूडा के क्षेत्र में हूडा कराएगा तो फिर खनन विभाग का काम क्या है। दरअसल, अवैध खनन रोकने के लिए खनन विभाग, नगर निगम, हूडा और वन विभाग में समन्वय नहीं है। माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा जानबूझ कर किया जाना हो सकता है। अवैध खनन होने पर दूसरे महकमे खनन विभाग और खनन विभाग दूसरी संस्थाओं के अधिकारक्षेत्र का हवाला देकर कार्रवाई नहीं करते। अरबों रुपये का यह कारोबार नेता और अधिकारियों को खुश किए बिना नहीं हो सकता। इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक अवैध खनन की जितनी भी एफआईआर दर्ज कराई गई है उनमें शायद ही किसी में ठोस कार्रवाई हुई हो।

ऊंचागांव जामा मस्जिद में दिखा नवरात्र और रमजान का संगम हिंदू-मुस्लिमानों ने साथ तोड़ा ब्रत और किया इफ्तार



फरीदाबाद (मजदूर मोर्चा)

बल्लभगढ़ की ऊंचागांव जामा मस्जिद म